



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 26 दिसम्बर, 2000/5 पौष, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिकारी

शिमला-4, 26 दिसम्बर, 2000

संख्या 1-74/2000-वि००.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की बसूली) विशेषक, 2000 (2000 का 3086-राजपत्र/2000-26-12-2000--1,399. (4739) मूल्य : 1 रुपया।

विधेयक संख्या०क 14) जो आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2000 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरस्थापित हो चुका है, सर्व-संधारण की सूचनाथे राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

ग्रजय भण्डारी,
सचिव।

2000 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश लोक धन (देश की वसूली) विधेयक, 2000

राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम या इन निर्मित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य निगम अथवा सरकारी कम्पनी या बैंककारी कम्पनी के कलिपय देयों की शीघ्र वसूली से मन्त्रिनियमित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकायावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निर्णयित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक धन (देश की वसूली) अधिनियम, 2000 है ।

(2) इसका विस्तार मम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश गज्ज दर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि आदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

संविधान नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ ।

परिभाषाएं ।

(क) "बैंककारी कम्पनी" से,—

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी ;

(ii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;

(iii) भारतीय स्टेट बैंक (भमनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक ;

(iv) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्गमित कृषि वित्त निगम सीमित कम्पनी ;

(v) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ;

(vi) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक ;

(vii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को धारा 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंककारी संस्था ;

(viii) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन गठित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ; या

(ix) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है;

(ख) "कलकटर" से, जिले का कलकटर अभिप्रेत है और इस अधिनियम के अंतीं राज्य सरकार द्वारा कलकटर के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति इस के अन्तर्गत है ;

1949 का
10

1955 का
23

1959 का
38

1956 का
1

1981 का
61

1970 का
5

1949 का
10

1976 का
21

1980 का
40

- (ग) "निगम" से, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वधीन या नियन्त्रणाधीन, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कोई अन्य निगम भी है;
- (घ) "वित्तीय सहायता" से, निम्नलिखित के लिए दी गई कोई वित्तीय सहायता अभिप्रेत है,—
- व्यवसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए ; या
 - आवासिक भवन के निर्माण के लिए ; या
 - पेयजल, कूहल या पाहा नाईन की व्यवस्था करने के लिए ; या
 - पशुपालन, कृषि या बागवानी के विकास के लिए ; या
 - किसी आमीण या कुटीर उद्योग, औद्योगिक उपकरण या कृषि उद्योग की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, नवीकरण करने या चलाने के लिए ; या
 - किसी अन्य प्रकार के योजनाबद्ध विकास के प्रयोजनों के लिए ; या
 - विपत्ति से राहत के लिए ; या
 - राष्ट्रीय उधार छातवृत्ति स्कीम के अधीन ऋण के लिए ; या
 - वृत्तिक/विशेषज्ञीय प्रशिक्षण, जैव राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, जिसके सम्बन्ध में छातवृत्ति/वृत्तिका लोक निधि से संदर्भ की जाती है और राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा दी जाती है;
- (ङ) "सरकारी कम्पनी" से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है और जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-ममय पर इस रूप में अधिसूचित किया जाता है;
- (च) "औद्योगिक उपकरण" के अन्तर्गत, माल के विनिर्माण, परिरक्षण, भण्डारकरण या प्रसंस्करण अथवा खनन या होटल उद्योग अथवा याक्रियों या माल का परिवहन या विद्युत या विद्युत शक्ति के किसी अन्य रूप में उत्पादन या वितरण अथवा मालीनों, यानों, जलयानों, नौकायान, ट्रेनरों या ट्रक्टरों के रख-रखाव, मरम्मन, परीक्षण या मफाई-धूलाई मालीनों या बिजली की सहायता से किन्हीं वस्तुओं के समंजन, मरम्मत या पैकिंग या मछली पकड़ने या उसके रख-रखाव के लिए तट सुविधाओं की व्यवस्था करने या भूमि के किसी नलन क्षेत्र का औद्योगिक सम्पदा के रूप में विकास करने या औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि के लिए विशेष या तकनीकी जानकारी या अन्य सेवाओं को व्यवस्था करने के लिए कोई उपकरण है;

स्पष्टीकरण— "माल का प्रसंस्करण" पद के अन्तर्गत किसी सामग्री को शारीरिक, दाँतिक, रसायनिक, विद्युत या इसी प्रकार की अन्य क्रिया के अधीन कर्त्ते किसी वस्तु के उत्पादन, तयार करने या बनाने का कोई कार्य या प्रक्रिया है;

- (उ) "श्रावोविन स्कीम" में, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वह प्रयोगित स्कीम अभिप्रेत है जिसके अधीन सम्बद्ध सरकार द्वारा तो,—

1951 का
63

1956 का
1

- (i) निगम या सरकारी कम्पनी को ऋण, अग्रिम, अनुदान या महायकी के संबंधित रण के प्रयोजन के लिए या माल के उधार पर या अवकाश पर विक्रय प्रयोजन के लिए अग्रिम धन देती है ; या
- (ii) ऋण, अग्रिम, अनुदान या महायकी के संदाय या उधार पर या अवकाश पर विक्रीत माल की कीमत के संदाय की प्रत्याभूति देती है या प्रत्याभूति देने के लिए महसूल होती है ; और
- (न) "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

3. (1) जहाँ कोई व्यक्ति या तो मूल ऋणी के रूप में या प्रतिभूति के रूप में या प्रत्याभूतिदाता के रूप में निम्नलिखित में पक्षकार है—

- (क) (i) राज्य सरकार, सरकारी कम्पनी, बैंककारी कम्पनी या निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उस करार के अधीन दिए गए ऋण, अग्रिम, अनुदान या महायकी, वित्तीय सहायता, वृत्तिका या छात्रवृत्ति से सम्बन्धी या विक्रीत माल के उधार के बारे में या अवकाश में सम्बन्धी किसी करार या बंधपत्र का ; या
- (ii) यथास्थिति, राज्य सरकार, बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन दिए गए ऋण, अग्रिम, अनुदान या महायकों से सम्बन्धी या विक्रीत माल के उधार के बारे में या अवकाश से सम्बन्धी किसी करार का ; या
- (ख) मीदोगिक उपकरण द्वारा दिए गए ऋण के बारे में राज्य सरकार, सरकारी कम्पनी, बैंककारी कम्पनी या निगम द्वारा दी गई प्रत्याभूति से सम्बन्धी किसी करार का ; या
- (ग) किसी करार का, जो यह उपबंधित करता है कि तद्धीन भरकार को देय कोई धन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ; या
- (घ) राज्य सरकार द्वारा या के माध्यम से दिए गए माल या किसी अन्य वस्तु के विक्रय या वितरण के किसी करार,
- और ऐसा व्यक्ति—
- (i) ऋण, अग्रिम, वृत्तिका या छात्रवृत्ति का उक्तकी किसी किस्त या ब्याज के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम करता है ; या
- (ii) अनुदान की शर्तों के अधीन, अनुदान या उसके किसी प्रभाग का प्रतिदाय करने का दायी होने पर ऐसे अनुदान या उसके प्रभाग या किस्त के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम करता है ; या
- (iii) माल या किसी अन्य वस्तु की कीमत या उसके ब्याज के संदाय का दायी होन पर, उसके या उसके भाग का संदाय करन में अतफल रहता है ; या

कृतिपथ
देय की
भू-राजस्व
की बकाया
के रूप में
वसूली ।

(iv) अन्यथा करार के निवंशों का असंपालन करने में अनफल रहता है; तब, राज्य सरकार की दशा में ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन निमित्त प्राधिकृत किया जाए, और बैककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी की दशा में, उक्ता प्रबन्ध निवेशक या इस निमित्त विनिर्दिष्ट: प्राधिकृत कोई अय अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से जात हो जो मण्डलीय प्रबन्धक की पंक्ति में नीचे का न हो। तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के अधीन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिक्रिया प्रभाव डाले विना, कलकटर को, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राशि को विणत करने हुए और यह अनुरोध करने हुए प्रमाणपत्र भेज सकेगा कि कार्यवाहियों के बच्चे सहित ऐसी कोई राशि या कोई अन्य राशि वसूल की जाए मात्र यह भू-राजस्व की बकाया हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन भेजा प्रमाणपत्र उसमें विवरणित विषय का निश्चायक स्वूत होगा और कलकटर ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर उस विवरणित रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(3) उप-धारा (1) की कोई भी वात, किसी बन्धक, भार, गिरवी या किसी अन्य विलंगम द्वारा संजित किसी सम्पत्ति में, राज्य सरकार, बैककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी के हित पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(4) जहाँ उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की सम्पत्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार, बैककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी के पक्ष में किसी बन्धक, भार, गिरवी या अन्य विलंगम के अधीन है, वहाँ तब—

(क) माल की गिरवी की दशा में इस प्रकार गिरवी रखे माल के विक्रय के लिए कार्यवाहियों की जाएंगी और यदि ऐसे विक्रय के अगम, देय रकम से कम है, तो ऐसे व्यक्ति की अन्य सम्पत्ति के विश्वद अविशेष की वसूली के लिए कार्यवाहियों की जाएंगी :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि, यथास्थिति, इसको या बैककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी को देय रकम की वसूली की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो यह कारणों को अभिनिवित करते हुए तब गिरवी माल पहले या उसी समय अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाहियों करने के लिए निश्च दे सकेंगी मात्र कार्यवाहियों गिरवी रखे माल के विक्रय के लिए की जाती है।

(ख) स्थावर सम्पत्ति पर बन्धक, भार या अन्य विलंगम की दशा में, यथास्थिति, ऐसी सम्पत्ति या, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति का उसमें हित, उस व्यक्ति में देय राशि की वसूली के लिए कार्यवाहियों में पहले विक्रीत किया जाएगा और अन्य कोई कार्यवाहियों के बीच तभी की जा सकेंगी यदि कलकटर प्रमाणित करे कि प्रथमतः वर्णित प्रक्रिया द्वारा युक्ति-युक्त समय के भीतर देय राशि की वसूली की कोई संभावना नहीं है।

(5) जहाँ सरकारी कम्पनी, बैककारी कम्पनी या निगम के देयों के अतिरिक्त, धारा 3 में वर्णित व्यक्ति में सरकारी देय वसूलीय हों, वहाँ भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली में सरकारी देयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. धारा 3 के अधीन कलहन को सेवानी का उपभोग करने वालों कोई वैकारी कम्प नहीं, निगम या सरकारी कम्पनी ऐसे दर पर राज्य सरकार को मंगड़ण प्रभार संदर्भ करने से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

5. (1) हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय को ब्रूली) अधिनियम, 1973 एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई वात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्यानी उपचरनी के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1973 (1973 का 22) राज्य, या निगम अथवा सरकारी कम्पनी को संदेश कर्तिष्य देयों की भू-राजस्व की बकाया के रूप में देयों की शोध वसूली के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध अनुसूचित बैंकों के देयों की वसूली के लिए उसी रीति में उपबंध नहीं करता है। वर्तमानतः, विभिन्न बैंकों द्वारा ऋणों का भारी बकाया वसूली के लिए लंबित पड़ा है। क्योंकि ऐसी वसूली को विनियमित करने व कानूनों में लम्बी प्रक्रिया का उपबंध होने के कारण, न्यायालय दावों को अन्तिम रूप देने के लिए पर्याप्त समय लेते हैं। इन बैंकों ने राज्य सरकार को उपर्युक्त अधिनियम में उपयुक्त उपबंध करने के लिए अनुरोध किया है ताकि लम्बित वसूलियां भू-राजस्व की बकाया के रूप में शोध की जा सके। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ऋण छावनी तक स्थिर और राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा दी गई वृत्तिक/विशेषज्ञीय प्रशिक्षण के अधीन बंध-पत्र धन या ऋणों की वसूली के लिए उपयुक्त उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस से उपबंधों को पुनर्विलोकित और पुनः अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिरकता :; 2000.

राजन सुशास्त्र;
प्रभारी मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबंध अधिनियमित किए जाने पर, राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम वा किसी सरकारी कम्पनी अथवा बैंककारी कम्पनी आदि की अपने देयों को भू-राजस्व की बकाया के रूप में बसूल करने को संगत करेगा। विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबंध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तंत्र द्वारा कार्यान्वयित किए जाएंगे। इसलिए, विधेयक के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राजकोष से कोई भी अतिरिक्त व्यय उपयोग नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4, राज्य सरकार को, कलक्टर की सेवाओं का उपभोग करने वाली बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी द्वारा दी जाने वाली संग्रहण प्रभार की दरों को अधिसूचित करने को मशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन आवश्यक और नामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2000.

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC MONEYS (RECOVERY OF DUES) BILL, 2000

A

BILL

to re-enact the law relating to the speedy recovery of certain dues of the State Government or the Himachal Pradesh Financial Corporation or any other Corporation notified by the State Government in this behalf or a Government Company or a Banking Company.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 2000.

(2) It extends to whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Banking Company” means,—

10 of 1949 (i) a Banking Company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 ;

23 of 1955 (ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955;

38 of 1959 (iii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

1 of 1956 (iv) the Agricultural Finance Corporation Limited, a company incorporated under the Indian Companies Act, 1956 ;

61 of 1981 (v) the National Bank for Agricultural and Rural Development, established under the National Bank of Agricultural and Rural Development Act, 1981 ;

5 of 1970 (vi) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 ;

10 of 1949 (vii) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 ;

21 of 1976 (viii) the Regional Rural Banks constituted under the Regional Rural Banks Act, 1976 ;

40 of 1980 (ix) a corresponding new Bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 ;

(b) “Collector” means a Collector of the District and includes any person appointed by the State Government to perform the functions of a Collector under this Act ;

Short title,
extent and
commen-
cement.

Defini-
tions.

(c) "Corporation" means the Himachal Pradesh Financial Corporation established under the State Financial Corporation Act, 1951 and includes any other Corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government which the State Government may, by notification, specify ;

63 of 1951

(d) "financial assistance" means any financial assistance rendered,—

- (i) for the purposes of vocational or technical training ; or
- (ii) for the construction of residential buildings ; or
- (iii) for providing drinking water, kuhl or pipe line; or
- (iv) for the development of animal husbandry, agriculture or horticulture; or
- (v) for establishing, expanding, modernising, renovating or running any village or cottage industry, industrial undertaking or agro industry ; or
- (vi) for purposes of any other kind of planned development; or
- (vii) for relief against distress; or
- (viii) for loans under the National Loans Scholarship Scheme ; or
- (ix) for professional'specialised training, as may be notified, in the Official Gazette, by the State Government, in relation to which scholarship/stipend is paid out of the public funds and is imparted by the institutions of the State Government ;

(e) "Government Company" means a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 and which is notified as such by the State Government from time to time;

1 of 1956

(f) "industrial undertaking" includes any undertaking for the manufacture, preservation, storage or processing of goods, or mining, or the hotel industry, or the transport of passengers or goods, or the generation or distribution of electricity or any other form of power or the maintenance, repair, testing or servicing of machinery, vehicles, vessels, motor boats, trailers or tractors or assembling, repairing or packing of any articles with the aid of machinery or power or fishing or providing shore facilities for fishing or maintenance thereof, or for the development of any contiguous area of land as an industrial estate or providing special or technical knowledge or other services for promotion of industrial growth ;

Explanation.— The expression "processing of goods" includes any act or process for producing, preparing or making an article by subjecting any material to a manual, mechanical, chemical, electrical or any other like operation ;

(g) "sponsored scheme" means a scheme sponsored by way of financial assistance by the State Government or the Central Government under which the concerned Government, either—

- (i) advances money to the Corporation or the Government Company for the purposes of disbursing loans, advances, grants or subsidies or for the purpose of sale of goods on credit or hire purchase ; or

91

(ii) guarantees or agrees to guarantee the payment of loan, advances, grant or subsidies or the payment of price of goods sold on credit or hire purchase; and

(h) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

3. (1) Where any person either as principal or as surety or as guarantor is a party—

(a) (i) to any agreement or bond, relating to a loan, advance, grant, subsidy, financial assistance, stipend or scholarship given under that agreement or relating to credit in respect of, or relating to hire purchase of goods sold by the State Government, Government Company, Banking Company, or Corporation by way of financial assistance ; or

(ii) to any agreement relating to loan, advance, grant or subsidy given under that agreement or relating to credit in respect of, or relating to hire purchase of, goods sold by the State Government, a Banking Company, a Corporation or a Government Company, as the case may be, under a sponsored scheme ; or

(b) to any agreement relating to a guarantee given by the State Government, Government Company, Banking Company or a Corporation in respect of a loan raised by an industrial undertaking ; or

(c) to any agreement providing that any money payable thereunder to the State Government shall be recoverable as arrears of land revenue ; or

(d) to any agreement to sell or distribute goods or any other article supplied by/or through the State Government and such person—

(i) makes any default in the repayment of the loan, advance, stipend or scholarship or any instalment or interest thereof ; or

(ii) having become liable under the conditions of the grant to refund the grant or any portion thereof, makes any default in repayment of such grant or portion or instalment thereof ; or

(iii) having become liable to pay the price of the goods or any other article or interest thereof, fails to pay the same or part thereof; or

(iv) otherwise fails to comply with the terms of the agreement;

then, in case of the State Government, such officers as may be authorised in this behalf by the State Government, by notification in the Official Gazette, and in the case of Banking Company, Corporation or the Government Company, the Managing Director or any other officer not below the rank of Divisional Manager specifically authorised in this behalf, thereof, by whatever name called, may without prejudice to any other mode of recovery under any other law for the time being in force, send a certificate to the Collector, mentioning the sum due from such person and requesting that such sum together with the costs of the proceedings or any other sum be recovered as if it were an arrear of land revenue.

Recovery
of certain
dues as
arrears of
land reve-
nue.

(2) A certificate sent under sub-section (1) shall be conclusive proof of the matter stated therein and the Collector on receiving such certificate shall proceed to recover the amount stated therein as an arrear of land revenue.

(3) Nothing in sub-section (1) shall affect any interest of the State Government, a Banking Company, a Corporation or a Government Company, in any property created by mortgage, charge, pledge or any other encumbrance.

(4) Where the property of any person referred to in sub-section (1) is subject to any mortgage, charge, pledge or other encumbrance in favour of the State Government, a Banking Company, a Corporation or a Government Company, as the case may be, then—

(a) in every case of a pledge of goods, proceedings shall first be taken for the sale of goods so pledged and if the proceeds of such sale are less than the sum due, then proceedings shall be taken for recovery of the balance against the other property of such person:

Provided that where the State Government is of the opinion that it is necessary so to do for safeguarding the recovery of the sum due to it or to a Banking Company, a Corporation or a Government Company, as the case may be, it may, for reasons to be recorded in writing, direct proceedings to be taken against the other property then the goods pledged before or at the same time as the proceedings are taken for the sale of goods pledged.

(b) in every case of a mortgage, charge or other encumbrance on immoveable property, such property or, as the case may be, the interest therein of the person referred to in sub-section (1) shall first be sold in proceedings for recovery of the sum due from that person and any other proceedings may be taken only if the Collector certifies that there is no prospect of realisation of the sum due through the first mentioned process within a reasonable time.

(5) Where Government dues are recoverable from the person mentioned in section 3 in addition to dues of Government Company, Banking Company or Corporation, priority will be given to Government dues in recovery as arrears of land revenue.

Collection charges.

4. A Banking Company, a Corporation or a Government Company availing the services of the Collector under section 3 shall pay collection charges to the State Government at such rates, as may be notified in the Official Gazette by the State Government, from time to time.

Repeal and savings.

5. (1) The Himachal Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1973 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1973 (Act No. 22 of 1973) makes provisions for speedy recovery of certain dues payable to the State, or Corporation or Government Company as arrears of land revenue. The existing provisions contained in the said Act do not provide for the recovery of dues of the Scheduled Banks in a like manner. At present, huge arrears of loans are lying pending for recovery by various Banks. The courts take considerable time in finalization of the cases because of the statutes regulating such recovery, provide for a lengthy procedure. These banks have made requests to the State Government for making suitable provisions in the aforesaid Act so that the pending recoveries could be effected expeditiously as arrears of land revenue. Further, it has also been proposed to make suitable provision for recovery of bond money or loans under the National Loan Scholarship Scheme and professional/specialised training imparted by the institutions of the State Government. This has necessitated the review and re-enactment of the provisions.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

RAJAN SUSHANT,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The ... , 2000.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, when enacted, will empower the State Government or Himachal Pradesh Financial Corporation or a Government Company or a Banking Company etc. to recover their dues as arrears of land revenue. The provisions contained in the Bill, when enacted, will be implemented through the existing Government machinery and thus for the implementation of the provisions of the Bill, no additional expenditure shall be incurred out of the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill empowers the State Government to notify the rates of collection charges to be paid to the State Government by the Banking Company, a Corporation or a Government Company availing the services of the Collector.

This delegation is essential and normal in character.

नियन्त्रक, मृदुग तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित